Development of Krishna Patnam Port in Nellore District as Fishing Harbour

4197. SHRI PASALA PENCHALAIAH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are considering to develop Krishna Patnam Port in Nellore District of Andhra Pradesh as fishing harbour with the collaboration of U.K. Government;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) the latest position and probable time of taking up the project ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The Krishna Patnam Fishing Harbour proposal is yet to be posed for assistance to the Government of U.K.

(b) The estimated cost of the scheme is about Rs. 15 crores. Major components are : fishing harbour, village roads, fishing vessels and marketing and processing facilities.

(c) The project can be taken up for implementation only after the scheme has been sanctioned.

उत्तर प्रदेश में भुखमरी और बाढ़

4198. **श्री जैनुल बशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भुखमरी और बाढ़ के कारण भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो भुखमरी और बाढ़ के कारण अलग-अलग कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है और इसके लिए सहायता स्वरूप कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और कितनी धनराशि वास्तव में दी गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। 27-9-1983 को उत्तर प्रदेश सरकार से सूखा और बाढ़ों पर एक-एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) राज्य सरकार ने सूखे के लिए 36.9 करोड़ रुपये और बाढ़ राहत कार्यों के लिए 566.93 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है। राज्य के 13 मिलों में लगभग 17.75 लाख हैक्टार में फसल शुरू की गर्मियों के महीनों में वर्षा न होने के कारण या तो क्षतिग्रस्त हुई या बोई नहीं जा सकी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ के कारण हुई निम्नलिखित क्षति सूचित की है :—

1. प्रभावित जनसंख्या	153.27 लाख
2. प्रभावित सस्यगत क्षेत्र	24.02 लाख हैक्टार
3. क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए मकानों की संख्या	3.89 लाख
4. मृत मनुष्य	511
5. मृत पशु	1835

(ग) एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया है और उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकतम केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति लम्बित होने तक भारत सरकार ने राज्य सरकार को तत्काल राहत व्ययों की पूर्ति करने के लिये साधनोपाय अग्रिम के रूप में 30 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास तत्काल व्यय की पूर्ति के लिये 1080 लाख रुपये का सीमान्त धन भी है।